भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक
7–8–9 सितम्बर 2006
देहरादून (उत्तरांचल)

आन्तरिक सुरक्षा पर प्रस्ताव

यूपीए शासन के दो वर्ष बीत जाने के बाद आन्तरिक सुरक्षा पर संकट जैसा गहराया है वैसा पहले कभी नहीं था। वैसे भी आन्तरिक सुरक्षा यूपीए सरकार की प्राथमिकता कभी नहीं रही।

यूपीए द्वारा बनाये गए न्यूनतम साझा कार्यक्रम में आतंकवाद से संघर्ष करने जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद रोकने, सीमापार से हथियारों, विध्वंसकों, विस्फोटकों और गोलाबारूद के आवागमन को रोकने का कहीं जिक्र तक नही किया गया। उसमें वाममार्गी अतिवाद से संघर्ष करने हेतु देश की आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के संदर्भ में कोई चिंता नहीं जतायी गई। यूपीए के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा से संदर्भित सिर्फ एक बात कही गई थी और वह भी पोटा को हटाने से जुड़ी थी। यह यूपीए की इसी मनःस्थिति और घुटना टेकू नीतियों का ही परिणाम हैं कि देश के भीतर और बाहर ऐसे विध्वंसक और कट्टरवादी समूहों को बढ़ावा मिला जो आतंकवाद के विरूद्ध हमारे राष्ट्रीय प्रयास को चोट पहुंचाते हैं। इससे देश की सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिरा है और आतंकवाद के विरूद्ध लड़ने के उनके संकल्प में शिथिलता आई है।

राजग सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को दी गई उच्च प्राथमिकता एवं मंत्रियों के समूह की संस्तुतियों के कारण सुरक्षा प्रणाली मे आयी मजबूती से जो एक गति बनी थी उसे गंवा दिया गया है बल्कि पूरी प्रक्रिया उलट दी गई है। आन्तरिक सुरक्षा को आज केवल वोट बैंक की राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। देश का आतंकवाद के विरूद्ध लिया गया संकल्प राजनीतिक अनुकूलता बनाने की भावना का शिकार बन गई है।

यूपीए के राज में आतंकवाद की घटनाओं में बड़ी तेजी देखने में आई है। आतंकवादी जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के बाहर भी अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल रहे उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों विशेषरूप से महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडू, केरल, गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में अपने अड्डे बना लिए हैं। आईएसआई का नेटवर्क नये क्षेत्रों में फैलता जा रहा है। पिछले एक वर्ष में उन्होंने ऐसी जगहों को निशाना बनाया है जहां भारत को सबसे अधिक चोट पहुंचती है।:– अयोध्या (5 जुलाई 2005), श्रीराम का जन्मस्थान जिसमें हिन्दुओं की भावना जुड़ी

है; दिल्ली (29 अक्टूबर 2005), राजनीति का केन्द्र, बंगलौर (28 दिसम्बर 2005), भारत की तकनीकी विकास की राजधानी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग का हृदय स्थल, वाराणासी (7 मार्च 2006), हिन्दुओं का एक पवित्र नगर, नागपुर (01 जून 2006) आरएसएस का मुख्यालय जो भारतीय राष्ट्रवाद का एक प्रतीक है, तथा मुम्बई (जुलाई 11, 2006) भारत की आर्थिक राजधानी।

इन हालिया हमलों में सबसे चिंताजनक बात यह है कि सीमा–पार आतंकवाद को अंजाम देने वाले लोगों द्वारा इसी देश के संसाधनों (मानवीय एवं भौतिक) का प्रयोग करना। पाकिस्तान ने गड़बड़ी फैलाने के लिए अपने संसाधनों को भारत में फैला दिया है।

मालेगांव में हुए कल के विस्फोट, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गये, आतंकवादियों की कार्रवाई और सरकार की बेरूखी के साथ निकम्मेपन का बड़ा सटीक उदाहरण है। ये हमले अशांति पैदा करने, तनाव को बढ़ाने, निर्दोष लोगों की हत्या करने तथा भारत की सार्वभौमिकता पर आक्रमण करने की दृष्टि से किए गये हैं। गुप्तचर एजेंसियों को हो रही घटनाओं का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। गृहमंत्री ने एक अप्रेरणादायी तथा चलताऊ बयान दिया है। सरकार से किसी भी दृढ़ता की उम्मीद नहीं की जा सकती। यूपीए सरकार की घुटना टेक नीतियों के कारण ये देश और देश की जनता पीड़ा सहने के लिए मजबूर है और रहेगी।

प्रारम्भ में अधिकांश आतंकी हमलों में पूरी तरह सीमापार ताकतों का हाथ होता था। आजकल इसी जमीन पर पले बढ़े आतंकवादियों द्वारा सीमापार के आतंकियों को आर्थिक सहायता एवं सहयोग से आतंकी घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है तुष्टिकरण की राजनीति और देश में बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से हुई अवैध घुसपैठ यह आबादी स्थानीय जनता के आवरण में देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गई है। ऐसे आतंकवादियों द्वारा अंजाम दी गई। ताजा घटना है। मुम्बई ट्रेन धमाके। जांच के नतीजे अभी तक सामने नहीं आये हैं। इस घटना से दो नये ट्रेंड सामने आये हैं। पहला यह कि यह धमाके बड़े ही पेशेवर अंदाज में किए गये हैं और दूसरा सूचना एवं जांच मशीनरी पूरी तरह असफल साबित हुई।

इन एजेंसियों को जो राजनीतिक संकेत दिए गये है वे भी काफी चिंताजनक है। उन्हें आतंकवाद के विरूद्ध अधिक तत्परता नहीं दिखाने के लिए कहा जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि आतंकवादियों के खात्में में पिछले 2 वर्षों में 56 फीसदी कमी देखने में आयी है। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अपनायी जाने वाली तुष्टिकरण नीति और वोट बैंक की राजनीति के चलते सिमी, हिजबुल मुजाहिदी, अहले हदीस, अल–उम्मा और दीनदार अंजुम जैसे संगठन मजबूत हो रहे हैं। कई कम प्रसिद्ध स्थानीय संगठन भी देश में जहां तहां पैदा हो गये हैं जो युवाओं को कट्टरवादी प्रचार के जरिए प्रभावित कर दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं।

पोटा राजग सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून था जिसका उद्देश्य, आतंकवादियों और उनके सहयोगियों शीघ्र प्रक्रिया अपनाते हुए, दण्डित करना था।

यूपीए द्वारा इस कानून को समाप्त करके आतंकवादियों के विरूद्ध नरम रवैया अपनाने का संदेश दिया गया। आतंकवादियों से निपटने के लिए एक नरम कानून क्यों रहे? वोटबैंक की राजनीति के लिए पोटा को समाप्त करके यूपीए ने आतंक के विरूद्ध लड़ाई में आत्मसमर्पण कर दिया है। कांग्रेस एवं वाम मोर्चा द्वारा कोयम्बटूर बम धमाकों के प्रमुख आरोपी को छुड़ाने के लिए केरल में एक प्रस्ताव का समर्थन करना वोट बैंक राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की बलि चढ़ाने का एक उदाहरण है। संगठित अपराध पर लगाम कसने के लिए राज्यों में बने कानूनों को केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी देने में विफल रहने का संबंध भी वोट बैंक राजनीति से जुड़ा है।

जम्मू एवं कश्मीर में शान्ति प्रक्रिया में यूपीए सरकार अंधेरे में हाथ–पांव मार रही है। जम्मू एवं कश्मीर को लेकर संवाद की प्रक्रिया राजग द्वारा प्रारम्भ हुई थी। राजग सरकार के शासनकाल में हुई दो दौर की बातचीत में कुछ सकारात्मक कदम उठाये गये थे। किसी निश्चित सोच के अभाव में शांति प्रक्रिया बाधित हो गई है। यहां तक कि हुर्रियत नेताओं ने भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए इंकार कर दिया। सरकार द्वारा की गई गलतियों को सुधारने के बजाय, प्रधानमंत्री ने कश्मीर पर बातचीत करने के लिए विभिन्न समूहों के गठन की घोषणा की है। केन्द्र–राज्य सम्बंधों के लिए गठित समूह के सम्मुख स्व–शासन से लेकर 1953 के पूर्व की स्थिति बहाल करने जैसी मांगे रखी जा रही है। पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि भारत ने उससे जम्मू एवं कश्मीर में 1953 से पूर्व की स्थिति बहाल करने संबधित एक प्रस्ताव दिया है। जम्मू एवं कश्मीर को संवैधानिक रूप से पूरी तरह भारत में मिलाने के बजाय एक उल्टी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। उल्फा के साथ बातचीत की प्रक्रिया को सरकार के भी अकुशल रवैये के चलते नुकसान पहुंचा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वार्ता कर रहे हैं। जिसमें उल्फा नेताओं की सबसे– निचली पायदान ने भी हिस्सा नहीं लिया।

पिछले कुछ दिनों में संवेदनशील सुरक्षा एजेंसियों में विदेशी जासूसों की घुसपैठ का खतरा काफी बढ़ गया है। सेनाओं के महत्वपूर्ण अंगो, राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय तथा रॉ की सुरक्षा से समझौता किया गया है। जासूसी को रोकने के लिए बनी संस्थाओं को अलविदा कह दिया है।

उदाहरण के लिए नेवी वार रूम लीक के कारण हमारे 2020 तक की सभी भावी कार्य योजनाएं और खरीद योजनाएं खतरे में पड़ गई हैं। इस घटना के तार 'स्कोंपीयन सौदे' के भी जुड़े हुए हैं। इन सूचनाओं को किसे दिया जा रहा था और इनसे अन्तिम रूप में किसे लाभ पहुंचना था इसका पता अभी लगना बाकी हैं।

वाम मार्गी आतंकवाद की स्थिति भी भयावह हो गई है। वाम आतंकी घटनाओं के चलते होने वाली मौतों के मासिक औसत में पिछले वर्षों की तुलना में पचास फीसदी वृद्धि दर्ज की है। न केवल मौतों में वृद्धि हुई है बल्कि इन हमलों की वयापकता से भी वाम अतिवाद की बढ़ती ताकत का अनुमान भी लगता है। 1970 के दशकों की स्मृतियों में अंकित माओवाद फिर हमारे सामने बदले की भावना से खड़ा हुआ है और इससे देश के 160 से अधिक जिले और तेरह राज्य प्रभावित है।

माओवादी समूह गुपचुप तरीके से चौंकाते हुए अपनी योजनाओं का अंजाम देते हैं। वे बड़े समूहों में हमले करते हैं। बिहार में जहानाबाद, मधुबन, उड़ीसा के कोरापुट और गजपति, छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके तथा झारखण्ड के गिरीडीह में हाल में हुए हमलों से माओवादी हिंसा का सामना करने की आवश्यकता रेखांकित होती है। इस अभियान के सैन्यीकरण से इसकी मारक क्षमता बढ़ी है। इनके द्वारा हथियारों की प्राप्ति, अपना सामाजिक आधार बढ़ाने और इनके विभिन्न समूहों द्वारा गतिविधियों के बीच आपसी तालमेल बढ़ना निश्चित रूप से राष्ट्रीय चिंता का कारण है।

कांग्रेस और राजद जैसे यूपीए के घटक दलों ने इन माओवादियों से वर्ष 2004 के चुनावों में एक राजनीतिक सैदा तय करने का भी प्रयास किया था। चुनावों के बाद उन्होंने माओवादियों को खुली छूट दी और अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई।

कांग्रेस सरकार ने IMDT Act 1984 बनाया था। यह कानून बांग्लादेश से असम और अन्य इलाकों में होने वाली अवैध घुसपैठ को वैध बनाने के लिए बनाया गया था। इसने अवैध घुसपैठियों की पहचान और निष्कासन की प्रक्रिया को दुरुह और लगभग असम्भव बना डाला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कानून को समाप्त किए जाने के बाद सरकार ने इस कानून को Foreigners' Tribunal Order में संशोधन के माध्यम से फिर लागू कर दिया। यदि यह कानून भारत के संविधान में रहेगा तो इसका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

पूर्वोत्तर में विध्वंसक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। हाल ही में बांग्लादेश राइफल्स ने कछार जिले के एक भारतीय गांव पर हमला किया। इम्फाल में स्थित इस्कॉन मन्दिर पर हमला हुआ। इस घटना की जारी जांच कभी तक किसी भी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रही है।

इस सरकार का सुरक्षा के मोर्चे पर होना राष्ट्रीय चिंता का एक प्रमुख विषय है। हमारे राष्ट्रीय संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च अधिक परन्तु परिणाम बहुत कम देखने में आया है। जब तक सत्तासीन यूपीए सुरक्षा मुद्दों से जुड़ी अपनी नीति को वोट बैंक राजनीति से मुक्त नहीं करती राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में ही रहेगा। भाजपा इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय मत तैयार करने के लिए अपना अभियान जारी रखेगी जिससे यह सरकार सुरक्षा प्रबंधन के मामले में एक बड़ा नीतिगत परिवर्तन लाने के लिए मजबूर हो।